

वन्य-जीव रेस्क्यू सेंटर विकसित करने मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, कहा-

वनतारा जैसे नवाचारों से वन्य-जीव संरक्षण और ईको-सिस्टम बनेगा

- ▶ चीतों के पुर्नस्थापन की तैयारी
- ▶ वनवासियों के अधिकारों का किया जा रहा सम्मान

भोपाल, देशबन्धु। राज्य में 'जियो और जीने दो' को भावना को केंद्र में रखकर सह-अस्तित्व आधारित को-सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे न केवल जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और वनवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में कई नवीनवाचार किए जा रहे हैं इनमें वन्यजीव अभयारण्यों के संरक्षण और प्रबंधन में उच्च तकनीकी कार्यप्रयोग, गुजरात के 'वनतारा' से प्रेरित रेस्क्यू सेंटर, दुर्लभ जीवों जैसे चीते, घड़ियाल एवं कछुओं के एक अभयारण्य से दूसरों में पुनर्संस्थापन और संरक्षित क्षेत्रों की फेंसिंग शामिल हैं। डॉ. यादव ने आज



वन विभाग के अधिकारियों को गुजरात के 'वन्तारा' वन्यजीव पुनर्वास केंद्र का अध्ययन कर प्रदेश में ही ऐसा ही रेस्क्यू और एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल वन्यजीवों के संरक्षण और पुनर्वास में एक नई मिसाल पेश करेगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश के घने वनों और वन्यजीव पर्यटन को राजस्व वृद्धि का एक प्रमुख माध्यम बताया। उन्होंने वन अधिकारी-कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाओं और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की।

वन्तोंने यह भी बताया कि वन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों से प्रदेश में वन क्षेत्र और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में वन ग्रामों की राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है। जैव-विविधता को बढ़ावा देने के लिए कई स्थलों को जैव-विविधता विरासत घोषित किया गया है। वन-अग्नि की घटनाओं पर विभाग की प्रतिक्रिया अब पहले से अधिक त्वरित हुई है, जो प्रभावी वन प्रबंधन को दर्शाता है।

अफ्रीका से लाए चीतों की कृपे

में सफल पुनर्स्थापना के बाद इन चीतों को प्रदेश एवं देश के दूसरे अभयारण्यों में बसाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा चुकी है। प्रदेश के बूटेलखंड वन क्षेत्रों में फैले वीरगंगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीता पुनर्स्थापना की तैयारियां चल रही हैं, जिससे जैव विविधता में वृद्धि होगी। जलीय जीव संरक्षण के रूप में नर्मदा में महाशीर मछली जैसे जलजीवों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। चंबल में कछुआ, मगरमच्छ एवं घड़ियाल एवं गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए केंद्र पहले से ही स्थापित हैं। संरक्षित क्षेत्रों के लगभग 160 किलोमीटर क्षेत्र में फेंसिंग की जा रही है। इससे वनजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। डॉ. यादव ने कहा कि टाइगर रिजर्व की घोषणा से जनजातीय समुदायों और वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और उनका पूर्ण सम्मान किया जाएगा। सह-अस्तित्व के लिए सह-प्रबंधन की नीति अपनाई जाएगी और जहां आवश्यक होगा, वहां पुनर्वास की सही स्थिति व्यवस्था की जाएगी।

भारत-जर्मनी सहयोग से सतत
विकास लक्ष्यों पर राज्य
स्तरीय कार्यशाला आज

भोपाल, देशबन्धु। सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करने में मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी क्रम में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में निजी उद्योग की भूमिका और सहभागिता को बढ़ाने के लिए भारत जर्मन सहयोग परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा विशेषज्ञों की राष्ट्रीय कार्यशाला भोपाल के कोर्टयार्ड हॉल मैरिट भोपाल में 3 जुलाई को सुबह 10 बजे से आयोजित की गई है।

कार्यशाला में मध्यप्रदेश के विभिन्न विभाग, जिलों के प्रतिनिधियों, नीति आयोग, जर्मनी की संस्था जीआईजेड के प्रतिनिधियों से सतत विकास के लक्ष्यों और उनके स्थानीयकरण के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में जर्मन दूतावास और यूएनडीपी के प्रतिनिधि, भारत जर्मन सहयोग परियोजना की प्रमुख श्रीमती हेनरी पेईचर्ट, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार राजीव कुमार सेन और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन से जुड़े विषय विशेषज्ञ, आर्थिक सलाहकार, कॉर्पोरेट भागीदारों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 4 को करेगा जनसुनवाई

भोपाल, देशबन्धु। प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जातियों को केन्द्र की सूची में शामिल करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 4 जुलाई 2025 को भोपाल में जन सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर और आयोग के सदस्य भूवन भूषण कमल जनसुनवाई करेंगे।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसुनवाई राज्य अतिथि गृह (व्हीआईपी गेस्ट हाउस) लालघाटी में 4 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से प्रारंभ होगी। इसमें मध्य प्रदेश की पिछड़े वर्ग की 32 जातियों (जो राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में हैं, किन्तु केन्द्र की सूची में नहीं हैं।) को केन्द्र की सूची में शामिल करने पर सुनवाई करेंगे।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान से उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने की चर्चा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में कार्यों, नवाचारों और प्रगति से अवगत कराया



भोपाल, देशबन्धु। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने बुधवार को भोपाल में भेंट कर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को लेकर सारगर्भित चर्चा की।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के नीतिगत निर्णयों, शिक्षा में किए जा रहे कार्यों एवं नवाचारों से अवगत कराया। श्री परमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में प्रदेश के समस्त जिलों में स्थापित

किए गए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और उनमें भारतीय ज्ञान परम्परा प्रकोष्ठ की स्थापना एवं प्रगति के सम्बंध में अवगत कराया। श्री परमार ने पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परम्परा के द्रुतगति से समावेश के लिए विभिन्न कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों से

प्राप्त अनुशंसाओं की जानकारी भी दी।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धरम सिंह को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में भारतीया भाषा के समन्वये के लिए हो रहे कार्यो की जानकारी से भी अवगत करायी। श्री परमानन्द विद्याधर्यो के गुणात्मक एवं सञ्ज्ञानात्मक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करने, उद्योगजन्यता को आश्रयकता अनुरूप रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की समन्वये शिक्षा बढ़ावा देने और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए किए जाने कार्यो एवं प्रगति से भी अवगत करायी।

इस अवसर पर स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ संजय गोयल, आयुक्त तकनीकी शिक्षा अवधेश शर्मा सहित उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष तोमर
ने खंडेलवाल को दी बधाई



निर्वाचित होने पर थपड़ दी है। श्री तोमर ने कहा है कि श्री खंडेलवाल का सौदीयकालीन संगठनात्मक अनुभव, संगठन के प्रति निष्ठा, प्रतिबद्धता, सजगता, सादरग्राही एवं कार्यकर्ताओं के प्रति आत्मीय लगाव उनके इस पद पर चयन को प्रेरित प्रतिक्रियाएं कायम हैं। विपक्ष अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि श्री खंडेलवाल के नेतृत्व में प्रदेश संगठन नई ऊर्जा, नवाचार और समन्वय के साथ और अधिक सजग होगा तथा कार्यकर्ताओं को केन्द्र में रखकर राष्ट्र-प्रथम के हमारे श्रेष्ठ की ओर अग्रसर होगा। श्री तोमर ने कहा कि उनका संगठनात्मक अनुभव कार्यकर्ताओं को नई दिशा प्रदान करने में सहायक होगा।



विधानसभा अध्यक्ष
नरेन्द्र सिंह तोमर से
बुधवार को विधानसभा
स्थित कार्यालय में
देशबन्धु के प्रबंध
संचालक पलाश सुरजन
ने मुलाकात कर उन्हें
‘मध्याप्रदेश के इतिहास
में महिलाएं’ नामक
पुस्तक भेंट की।

प्रथम पृष्ठ का शेष

हिमाचल में 16 जगह बादल.... क्षेत्र में बारिश में गांगर नदी में मछली पकड़ने गए 3 पहाड़ी कोखा बच्चे 4 घंटों तक फंसे रहे। अनामक नदी का जलस्तर बढ़ने से यह हदसा हुआ। नदी का जलस्तर कम हुआ, तो बच्चों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ओडिशा के बालासोर जिले में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। जिले के उत्तरी हिस्से में करीब 100 गांवों में सड़कों और खेतों में पानी भर गया है। बाढ़ का पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुश्रित पुजारी ने बताया कि उत्तरी ओडिशा की सभी बाढ़ नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन बहुत से गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। प्रशासन ने बालासोर, मयूरभंज और जाजपुर जिलों में राहत और बचाव काम तेज कर दिया है।

शेख हसीना की 6 माह.... गया है। अदालत की अवमानना के मामले में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण शकाली बुलबुल को भी दो महीने जेल की सजा सुना चुका है। 30 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक ताजुद्दीन इस्लाम ने न्यायाधिकरण के सामने मामले को पेरा किया था और शेख हसीना के बयान को पीढ़ितों और गवाहों को धमकाने की कोशिश बताया। जांचकर्ताओं ने फॉरेंसिक जांच के आधार पर बताया कि आईडियो विलंप में शेख हसीना की ही आवाज है।

संसद की सुरक्षा में सेंध.... का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों को खिलाफ पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं। पुलिस का तर्क था कि जमानत देने से इनके भागने, गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का जोखिम है। पुलिस ने आरोपियों को शक्तिशाली और प्रभावशाली बताते हुए कहा कि इनकी रिहाई जांच में बाधा डाल सकती है।

हम की भावना से बढ़ती है.... हे इसी से हमारी ताकत बढ़ती है। डॉ. यादव ने कहा कि हमारे संगठन पूर्व का एक चरण पूरा हो गया है, लेकिन हम सभी संकल्प लें कि अपने-अपने कार्य को निर्वह करके हुए मध्यप्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी संगठन प्रक्रिया बड़ी सहजता के साथ संपन्न हुई, लेकिन चुनौतियों ने अभी भी हमारे सामने हैं। हमारे विरोधी चाहें हैं पर पड़यंत्र रहे हों और इन पड़यंत्रों के बलबूते पर अपने सुर्खों को पूरा करना चाहें हैं।

अचानक मौतों की वजह.... आईसीएमएए की मदद से की जा रही है। इसका मकसद युवा वयस्कों की अचानक मौतों के कारण पता लगाना है। स्टडी के शुरुआत में आंकड़ों से पता चला कि दिल का दौरा या मायोकार्डियल इन्फेक्शन इस उम्र में अचानक मौत का प्रमुख कारण है। अहम बात यह है कि पिछले कई सालों में अचानक मौत के कारणों के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अधिकतर मौतों का कारण जेनेटिक प्यैथेसिस है। यह स्टडी अभी जारी है।

भोपाल, देशबन्धु ।



मध्यप्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित लोकचित्र मोबाइल ऐप ने अपनी पहली वर्षगांठ के साथ एक सराहनीय उपलब्धि दर्ज की है। बुधवार को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में इस अवसर पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ऐप के अब तक की सफलता, नागरिकों की भागीदारी और आगामी लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

[illegible]

डिजिटल गवर्नेंस का प्रभावी उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में ऐप के 5 लाख डाउनलोड सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, जिसके लिए व्यापक

जनवापरण और
प्रचार - प्रसार
अभियान चलाया
लोकपथ ऐप को
पर भी पहचान
ब 'कौन बनेगा
र' जैसे प्रतिष्ठित
म में अभिनेता
बच्चन ने इससे
परन प्रस्तुत किया।
स्पष्ट होता है कि
का यह नवाचार
में के लिए भी एक
बन चुका है। बैठक
अभियंता के पीएस
आर. बबलू, भवन
निगम के प्रमुख
अनिल श्रीरासवत,
वकास निगम के
प्रसाधक आर.के.

मेहरा, भोपाल परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय मस्के, आनंद राणे, बी.पी. बोरसी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे और ऐप के क्रियान्वयन व सुधार की दिशा में अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए।

